बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 177 ● नई दिल्ली ● बुधवार 29 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

फर्जी वसीयत केस में खरीदार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया 20 साल पुराना आपराधिक मामला

नई दिल्ली । वसीयत और जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इसके तहत कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 20 साल पुराने फर्जी वसीयत और जमीन धोखाधड़ी मामले में एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को खत्म कर दिया है। यह मामला तमिलनाडु के कड्डलूर जिले से जुड़ा है। यह केस 2004 की एफआईआर से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप था कि एक वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार कर जमीन बेची गई और असली उत्तराधिकारियों को उनके हक से वंचित किया गया। इस मामले में कई लोगों के साथ-साथ जमीन खरीदने वाले भी आरोपी बनाए गए थे। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे

दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने उठाई क्षेत्र की समस्याएं, डॉ. अनिल गोयल चुने गए सर्वश्रेष्ठ विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विशेष उल्लेख (नियम 280) के तहत भाजपा विधायकों ने मंगलवार को अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। इस बीच नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता, ट्रैफिक जाम, बेसहारा गायों, खाद्य पदार्थों में मिलावट और पीने के पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं पर विधायकों ने चिंता जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा शुरू की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना आभार जताया। साथ ही, विपक्ष को उसकी संकीर्ण सोच के लिए कठघरे में भी खड़ा किया। इसके साथ ही सदन में इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी गई। शुरुआत में विधायक शिखा शर्मा ने अपनी बात रखी। एक-एक करके अन्य विधायक भी अपनी बात कहते गए।

प्रमुख मुद्दे उठाए गए

अशोक गोयल ने नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की आसानी से उपलब्धता का मुद्दा उठाया।

शिखा राय ने खिड़की एक्सटेंशन और प्रेस एनक्लेव में लगने वाले जाम का मुद्दा उठाते हुए आउटर रिंग रोड तक लिंक रोड बनाने की मांग की।

श्याम शर्मा ने बेसहारा गायों की समस्या पर प्रकाश डाला और बताया कि उनके कार्यालय में रोजाना ×0-40 शिकायतें आती हैं।

संजय गोयल ने लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की मांग रखी।

कुलदीप सोलंकी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या उठाई।

गजेंद्र दराल ने अपने क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी का मुद्दा उठाया और जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने तथा पुरानी पानी की लाइनों को बदलने की

मांग की।

डॉ. अनिल गोयल ने पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर सुधार की मांग की।

भाजपा विधायक कुलवंत राणा और हरीश खुराना ने भी सड़कों पर जाम और बेसहारा गायों की समस्या को सदन में रखा।

डॉ. अनिल गोयल चुने गए सर्वश्रेष्ठ विधायक

विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में डॉ. अनिल गोयल की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने चयन समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी।

प्रथम विश्वयुद्ध में भारत की भूमिका

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ठीक एक सौ आठ वर्ष पूर्व 28 अप्रैल 1918 को इसी चैम्बर में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिनांक 27, 28 एवं 29 अप्रैल, 1918 को एक ऐतिहासिक युद्ध-सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में देशभर से लगभग 120 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। इनमें रजवाड़ों के शासक, प्रांतों के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय नेता सम्मिलित हुए थे। चर्चा का विषय था, प्रथम विश्वयुद्ध में भारत की भूमिका।

भारतीयों के विश्वास से किया गया छल

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का महत्व केवल इतना नहीं था कि यहां से भारतीय सैनिकों की भर्ती का आह्वान हुआ था , बल्कि यह भी था कि महात्मा गांधी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित थे और उन्होंने साम्रा'य के प्रति भारत के पूर्ण सहयोग का समर्थन किया था, इस विश्वास के साथ कि युद्ध में भारत की निष्ठा का पुरस्कार स्वराज के रूप में मिलेगा। परन्तु इतिहास गवाह है यह विश्वास छला गया। लगभग तेरह लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्वयुद्ध में साम्रा'य की ओर से मोर्चा संभाला। फ्लैंडर्स के खूनी मैदानों से लेकर गैलीपोली एवं मेसोपोटामिया तक मोर्चा संभाला। 74 हजार से अधिक भारतीय वीरों ने पराए देशों की मिट्टी में अपना रक्त सींचा। परन्तु कृतज्ञता के पुरस्कार के स्थान पर इसी सदन से भारत को मिला रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग का नरसंहार। अंत में उन्होंने कहा कि एक मिनट का मौन रखकर उन भारतीय वीरों को नमन करें, जिन्होंने एक सौ आठ वर्ष पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था।

आतिशी का बीजेपी पर दोतरफा हमला, महिला भत्ते और आप सांसदों के दल-बदल पर घेरा

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के चुनावी वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर मंगलवार को सवाल उठाए और आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने को ''असंवैधानिक'' करार दिया।

आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जनवरी में वादा किया था कि राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को उसी साल आठ मार्च से हर महीने 2,500 रुपये उनके बैंक खातों में मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं से अपने बैंक खातों को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए कहा गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि राशि जमा होने की पुष्टि का संदेश उन्हें मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आठ मार्च 2025 गुजर चुका है और अब आठ मार्च 2026 भी बीत गया लेकिन दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये नहीं आए हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस वादे के आधार पर महिलाओं के वोट हासिल किए और कहा कि शहर की महिलाएं अब भी इस वित्तीय सहायता के मिलने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले डीटीसी बसों में आसानी से सफर करती थीं, अब उन्हें 'पिंक कार्ड' के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि मुफ्त दवाओं, इलाज और जांच की सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस फैसले को स्वीकार करना संवैधानिक प्रावधानों और दलबदल विरोधी कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार किसी विलय को मान्यता देने के लिए मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है और इसके लिए विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। उनके अनुसार, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मूल पार्टी के विलय के बिना केवल दो-तिहाई सांसदों को किसी अन्य दल में शामिल होने की अनुमति देता हो।

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि यह कदम दलबदल विरोधी ढांचे का उल्लंघन करता है और वे इस मुद्दे को संवैधानिक और कानूनी माध्यमों से उठाते रहेंगे।

शशि थरूर ने माना महिला विरोधी है कांग्रेस- किरेन रिजिजू का बड़ा दावा, सांसद से मुलाकात को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर एक बड़ा दावा किया है। रिजिजू के अनुसार, शशि थरूर ने एक तरह से यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। यह बयान तब आया जब संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो सका। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था । किरेन रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि संसद सत्र के बाद उनकी और थरूर की मुलाकात हुई थी। उस दौरान थरूर ने मुस्कुराते हुए रिजिजू से कुछ बातें साझा कीं। रिजिजू के मुताबिक, थरूर ने कहा था, कांग्रेस पार्टी भले ही महिला विरोधी हो सकती है, लेकिन कोई भी महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेगी। रिजिजू ने कहा कि थरूर ने इस वाक्य के जरिए अपनी पार्टी की सच्चाई स्वीकार कर ली। रिजिजू ने आगे बताया कि उन्होंने थरूर के इस तर्क का जवाब भी दिया। उन्होंने थरूर से कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई आपको महिला विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन आपकी पार्टी निश्चित रूप से महिला विरोधी है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल दिखावे की राजनीति करती है। जब महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने की बारी आई, तो कांग्रेस ने पीछे हटने का रास्ता चुना। इस विवाद की जड़ 18 अप्रैल को थरूर की ओर से साझा की गई एक फोटो है। थरूर ने रिजिजू के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। थरूर ने तब लिखा था कि उन्होंने रिजिजू को यह समझा दिया है कि उन्हें कोई महिला विरोधी नहीं कह सकता। थरूर के अनुसार, रिजिजू ने उनकी इस बात को स्वीकार भी किया था। अब रिजिजू ने उसी बातचीत का दूसरा पहलू सामने रखकर कांग्रेस पर हमला बोला है। विवाद का मुख्य केंद्र महिला आरक्षण विधेयक है। सरकार का तर्क है कि 33 प्रतिशत कोटा लागू करने के लिए सीटों का परिसीमन जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि वह आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन परिसीमन के साथ इसे जोड़ना दक्षिण भारतीय रा'यों के साथ अन्याय होगा। विधेयक के गिरने पर रिजिजू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है। किरेन रिजिजू ने चेतावनी दी कि देश की महिलाएं इस कदम के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी।

महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में किया जोरदार प्रदर्शन

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पारित न होने के विरोध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने विधानसभा परिसर में मंगलवार को प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ने साजिश रचकर महिला आरक्षण रोकने का प्रयास किया है।

गुप्ता ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, लेकिन सत्ता के स्वार्थ में डूबे विपक्ष ने एक बार फिर महिलाओं से उनका अधिकार छीनने का काम किया। गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश की नारी शक्ति आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाएगी। जो महिला शक्ति का रास्ता रोकेगी, जनता उन्हें जवाब देगी। हम 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को निश्चित रूप से लागू कराएंगे और देश की नारी शक्ति को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया था। इस विधेयक के पारित न होने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे लेकर गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पूरे महिला समाज के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इसी की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

स्वरों में अमर विरासत- पं. राजन मिश्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि, बनारस घराने की परंपरा फिर हुई जीवंत

नई दिल्ली ।(इंद्रजीत सिंह) वाराणसी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान स्तंभ और पद्मभूषण से सम्मानित स्वर्गीय पंडित राजन मिश्रा जी की स्मृति में ÷राजन मिश्रा की स्मृति में संगीतमय संध्या÷ शीर्षक से नई दिल्ली और वाराणसी में दो दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन उनकी समृद्ध सांगीतिक विरासत और बनारस घराने की गौरवशाली परंपरा को समर्पित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उनके सुपुत्र पंडित ऋत्वेश मिश्रा ने बताया कि नई दिल्ली के प्रतिष्ठित स्टीन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित संगीतमय संध्या में देश के ख्यातिप्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमुख कलाकारों में पंडित भोला नाथ मिश्रा (वोकल), श्री अदनान खान (सितार), श्री जूहेब अहमद खान (तबला), पंडित भारत भूषण गोस्वामी (सारंगी), श्री जय शंकर मिश्रा (तबला) और श्री जाकिर धोलपुरी (हारमोनियम) शामिल रहे। कार्यक्रम तथा संयोजन रितभवी वाराणसी के सनबीम

का संचालन सुश्री प्रोडक्शन्स द्वारा किया गया। इसके उपरांत आयोजित दूसरी लहरतारा परिसर में राधिका मिश्रा ने किया संगीतमय संध्या में सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती दिव्या शर्मा और बनारस घराने के प्रख्यात गायक पं. अनुप मिश्रा ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सितार वादन में पं. नरेंद्र मिश्रा, तबला संगत में श्री श्रीकांत मिश्रा एवं पं. राजेश मिश्रा तथा हारमोनियम पर पं. पंकज मिश्रा ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन अमित मिश्रा ने किया।

वाराणसी का यह आयोजन रसिपा (राजन-साजन मिश्रा इंस्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स), सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस एवं कला प्रकाश के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। संगीत प्रेमियों के बीच एक भावुक माहौल भी देखने को मिला– जहां एक ओर पंडित राजन-साजन मिश्रा की अमर जुगलबंदी को मंच पर न देख पाने का गहरा दुख महसूस हुआ, वहीं दूसरी ओर पंडित साजन मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति और उनके सुपुत्र पंडित ऋत्वेश मिश्रा द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय संगीतमय संध्या ने उनकी यादों को पुनः जीवंत कर दिया। बनारस घराने की परंपरा, गुरु-शिष्य संबंध और सांगीतिक संस्कारों की अनूठी छवि इन आयोजनों में स्पष्ट रूप से झलकी। पंडित ऋत्वेश मिश्रा ने संगीत प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल श्रद्धांजलि हैं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस अमूल्य धरोहर को सहेजने का प्रयास भी हैं, जिसे पंडित राजन मिश्रा जी ने अपने जीवनभर साधना और समर्पण से विश्व पटल पर स्थापित किया।

क्या राहुल गांधी विपक्ष के विश्वसनीय नेता बन पाए हैं?

क्या राहुल गांधी जून 2024 में अपनी नियुक्ति के बाद से लोकसभा में एक विश्वसनीय नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं? लगभग दो साल बीत चुके हैं, वह कितने प्रभावी रहे हैं? क्या उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराया है और बजट समीक्षा के प्रति अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को बदला है? क्या उन्होंने इस दौरान रणनीतिक संचार और गठबंधन बनाने जैसे नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया है? ये प्रश्न उनके प्रभाव और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। राहुल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में की थी और उन्हें सफलताओं, चुनौतियों और असफलताओं तीनों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में कोई भी मंत्री पद न लेने का चुनाव करते हुए, जीत और हार के दौरान पर्दे के पीछे से पार्टी का मार्गदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी का एक प्रमुख पद पर आना काफी हद तक अपेक्षित था, जो पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को दर्शाता है। पार्टी की नियुक्तियों में उनका निर्णय अंतिम होता है। कई पार्टी सदस्यों ने उनके नेतृत्व को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा तो अन्य ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यह पार्टी में विकल्पों की कमी और नेहरू-गांधी परिवार पर उसकी निर्भरता को उजागर करता है। अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की भूमिका संसद के अंदर और बाहर सरकार की गलतियों को इंगित करना रही है। हालांकि, ऐसे महत्वपूर्ण समय भी रहे हैं जब वह अनुपस्थित थे। राहुल ने संविधान की रक्षा करने, आय असमानता को दूर करने और अन्य मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक मुखर, दृश्यमान भूमिका अपनाई है। उन्होंने औपचारिक भूमिका के अनुरूप अपनी छवि को फिर से गढ़ा है, जिसमें नौकरी सृजन, हाशिए पर पड़े समूहों की सुरक्षा और किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक दशक में पहली बार है कि किसी को कैबिनेट स्तर का पद मिला है। 2014 से, किसी भी विपक्षी दल ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 543 सीटों का 10 प्रतिशत हासिल नहीं किया था। यह विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में अपने पहले दिन, राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए कानून के शासन को बनाए रखने और विपक्ष के लिए आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, जाति जनगणना और किसानों के संकट जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वह मुख्य चुनाव आयुक्त और सी.बी.आई. प्रमुख जैसे अधिकारियों के चयन में भाग लेते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपक्ष का इन नियुक्तियों में दखल हो। राहुल की संसद में उपस्थिति अधिक टकराव वाली और मुखर हो गई है, जो सरकार को सीधे चुनौती देने के उनके रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है। सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा मोदी सरकार का जोर-शोर से बचाव करने के कारण संसद में शोरगुल वाले दृश्य सामने आए हैं। विधायी बहसों और पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके बढ़ते प्रभाव और असर को दर्शाती है, जो लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। एक सफल कदम उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसने उन्हें जनता के साथ घुलने-मिलने और उनकी समस्याओं को सीधे जानने की अनुमति देकर उनकी छवि को बढ़ाया। भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षित होने के बाद, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 2002 में मुंबई लौटने से पहले लंदन में काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त किया। गांधी को अक्सर उनके आलोचकों द्वारा 'अनिच्छुक राजकुमार' कहा जाता है, जो मानते हैं कि वह अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपनाने में संकोच करते हैं। हालांकि, कई लोग उन्हें लंबे समय से पार्टी में अनौपचारिक 'नंबर दो' मानते हैं। हालांकि, कुछ लोग नेतृत्व के लिए नेहरू-गांधी परिवार पर पार्टी की निरंतर निर्भरता को लेकर चिंतित थे। राहुल ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया और 2004 में अमेठी से एक सीट जीती। सितंबर 2007 में, वह पार्टी के महासचिव बने, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहीं। जनवरी 2013 तक, वह कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर पहुंच गए थे, जो उनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। आलोचकों का कहना है कि भले ही वह अब अधिक दृश्यमान हैं लेकिन पार्टी 2024 के अंत और 2025 में प्रमुख राज्य विधानसभा चुनाव हार गई। यह उनकी लोकप्रियता को वोटों में बदलने की क्षमता पर संदेह पैदा करता है। राहुल जून 2024 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जैसे-जैसे समय बीतता है, यदि वह क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन हासिल करने में विफल रहते हैं और स्थानीय राजनीति में संघर्ष करना जारी रखते हैं, तो वह समर्थन खो सकते हैं। विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक बनाया और 2024 के आम चुनाव में एक साथ काम किया। नतीजतन, विपक्ष ने अधिक सीटें जीतीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर दी। इसकेअतिरिक्त, महत्वपूर्ण आयोजनों में उनकी उपस्थिति और उनके ध्यान केंद्रित करने वाले विषयों के बारे में प्रतिक्रिया मिली है जिन्हें कुछ आलोचक कम महत्वपूर्ण मानते हैं। वह साधारण लोगों की चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाली गतिविधियों में शामिल होकर अधिक मिलनसार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग समूह उनके प्रदर्शन को अलग-अलग तरह से देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के कार्यकाल के दौरान, वह एक अधिक केंद्रित और स्पष्टवादी नेता बन गए हैं। हालांकि, क्या उन्होंने 'विश्वसनीयता' हासिल की है? यह व्यक्तिपरक मुद्दा है। समर्थक सुधार देखते हैं, जबकि विरोधी तर्क देते हैं कि उनकी शैली में कोई बदलाव नहीं आया है।

सम्पादकीय...

आनन्द सिंह की 'सुन्दरकाण्ड रहस्य मीमांसा' श्रीशिव शक्ति मंदिर को समर्पित

बलिया जनपद के सिंहपुर स्थित प्राचीन एवं प्रतिष्ठित श्रीशिव शक्ति मंदिर में एक गरिमामय आध्यात्मिक आयोजन के दौरान प्रख्यात लेखक आनन्द सिंह ने अपनी नवीन कृति 'सुन्दरकाण्ड रहस्य मीमांसा- आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विवेचना' मंदिर को भेंट की। यह पुस्तक आधुनिक वैश्विक कल्याण संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह के माध्यम से मंदिर प्रबंधन समिति की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती शांति देवी को औपचारिक रूप से प्रदान की गई। वर्ष 1958 के आसपास स्वर्गीय टीमल सिंह द्वारा स्थापित यह मंदिर क्षेत्र में आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्तमान में मंदिर का संरक्षण एवं सुव्यवस्थित संचालन आधुनिक वैश्विक कल्याण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। संस्थान के सतत प्रयासों से मंदिर परिसर में स्वच्छता, अनुशासन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरंतर विस्तार हुआ है, जिससे यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह, श्रीमती शांति देवी, अभिषेक सिंह, आदित्य सिंह, अनुप सिंह (किंटु सिंह), पूजा सिंह और आरुषि सिंह सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पुस्तक की प्रतियां भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार का संदेश भी दिया गया। लेखक आनन्द सिंह की यह कृति भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस के पंचम सोपान 'सुन्दरकाण्ड' पर आधारित एक गहन शोधपरक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति, साहस, विवेक और आत्मसमर्पण जैसे मूल्यों को आधुनिक संदर्भों में समझाने का प्रयास करती है। लेखक ने सुन्दरकाण्ड के प्रसंगों को प्रतीकात्मक दृष्टि से विश्लेषित करते हुए उन्हें मानव जीवन के आंतरिक संघर्षों और आत्मिक विकास से जोड़ा है। पुस्तक में 'सुन्दर' शब्द की पुनरावृत्ति, उसके अंक-तत्व और संरचनात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसे पूर्णता और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक बताया गया है। सागर लंघन, लंका प्रवेश, अशोक वाटिका में सीता की खोज और लंका दहन जैसे प्रसंगों को जीवन की चुनौतियों, भौतिक आकर्षण और आत्मिक शांति की खोज के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इस प्रकार श्रीहनुमान की यात्रा को आत्मा की विजय और अंतर्मन की साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने श्रीहनुमान के चरित्र को केवल पराक्रम का प्रतीक न मानकर एक आदर्श साधक, संत और दार्शनिक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है। 'बिनु सतसंग बिबेक न होई' जैसे प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक रूप में समझाया है। साथ ही, सुन्दरकाण्ड की फलश्रुतियों—सुख, संशय-निवारण और दुःख-नाश—को आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए यह बताया गया है कि राम-नाम का स्मरण मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का प्रभावी माध्यम हो सकता है। आनन्द सिंह की भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी पर आधारित है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का समृद्ध प्रयोग देखने को मिलता है। आवश्यकतानुसार उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों का संतुलित उपयोग उनकी लेखन शैली को और प्रभावशाली बनाता है।

नव-फ़ासीवाद, राष्ट्र की अवधारणा और एसआईआर

प्रभात पटनायक

भारत में नव-फासीवाद के उभार के दौरान, उससे जुड़ी कुछ विशेषताएं बहुत ही स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। ये बहुत ही आसानी से दिखाई देने वाली विशेषताएं हैं- असहाय अल्पसंख्यक समुदाय का ''पराया'' बनाया जाना और बहुसंख्यकों के बीच उसके प्रति नफरत पैदा किया जाना। इस अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर, शासन के आलोचकों पर, राजनीतिक विपक्ष पर, बुद्धिजीवियों पर, कलाकारों पर तथा अन्य पर शासन के अंगों और फासिस्ट गुंडों, दोनों के ही द्वारा दमनचक्र चलाया जाना। और इजारेदार पूंजी द्वारा और खासतौर पर इजारेदार पूंजी के एक नवीनतर तबके द्वारा खुल्लमखुल्ला, खालिस वर्गीय शासन। ये सभी सामान्य रूप से फासीवादी विशेषताएं, नव-फासीवाद के उभार के साथ आज भारत में खुल्लमखुल्ला देखी जा सकती हैं। लेकिन, इसके अलावा नव-फासीवाद की एक और कम स्वतःस्पष्ट किंतु महत्वपूर्ण विशेषता भी भारत में देखने को मिल रही है, जिस पर अब तक विशेष चर्चा नहीं हुई है। इसका संबंध राष्ट्र की अवधारणा मात्र से है। भारत जैसे देशों में, उप-निवेशवादविरोधी संघर्ष के बीच राष्ट्रवाद की जो अवधारणा विकसित हुई थी, यूरोप में वेस्टफेलियाई शांति संधियों की पृष्ठभूमि में जो राष्ट्रवाद विकसित हुआ था, उससे बुनियादी तौर पर भिन्न थी। राष्ट्रवाद की भारतीय अवधारणा ने, अपने यूरोपीय समकक्ष के विपरीत किसी ''अंदरूनी शत्रु'' की पहचान नहीं की थी। यह अवधारणा साम्राज्यवादी नहीं थी, जो कि हद से हद इलाकाई या टैरीटोरियल थी। और इसमें राष्ट्र का मकसद, बुनियादी तौर पर जनता के हितों की सेवा करना समझा जाता था न कि इसका उल्टा। लेकिन, नव-फासीवादी के साथ हम न सिर्फ यूरोपीय शैली के राष्ट्रवाद की ओर खिसक गए हैं (जिसे सबसे बढ़कर एक ''अंदरूनी शत्रु'' की निशानदेही में देखा जा सकता है) बल्कि यह बदलाव इतना भारी है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यह तो राष्ट्र की उस अवधारणा का ही सिर के बल खड़ा कर दिया जाना है, जो उप-निवेशवादविरोधी संघर्ष के दौरान विकसित हुई थी। इस शीर्षासन की अवस्था में, राज्य ही है जो जनता के ऊपर प्रतिष्ठित नजर आता है, न जनता उसके ऊपर। जनता की भूमिका ''राष्ट्र'' की सेवा करने की हो जाती है, न कि राष्ट्र की भूमिका जनता की सेवा करना। जनता के अधिकारों को कमतर बनाया जाता है, जबकि उसके कर्तव्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस तरह हमारा सामना दुहरे दैवीकरण से होता है। जनता से भिन्न, ''राष्ट्र'' का दैवीकरण होता है और यह पलटकर, ''नेता'' का दैवीकरण बन जाता है। ''नेता'' की कोई भी आलोचना, तथ्यतः एक राष्ट्र विरोधी कृत्य बन जाती है! राष्ट्र की अवधारणा का यह सिर के बल खड़ा किया जाना इस तथ्य में अभिव्यक्त होता है कि बजाए इसके कि जनता द्वारा अपने हितों की सेवा करने के लिए ''नेता'' का चुनाव किया जाए, जनता से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह ''नेता'' की सेवा करेगी। इसी विडंबना की चरम अभिव्यक्ति में जैसा कि हम आगे देखेंगे, अब तो ''नेता'' ही उस ''जनता'' का चुनाव करने लगा है, जिसका वह कथित रूप से नेता होगा। राष्ट्र की अवधारणा के सिर के बल खड़ा किए जाने की यह प्रवृत्ति अनगिनत उदाहरणों के जरिए, अनगिनत तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करती है। किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को ''मोदी जी की सेना'' कहकर संबोधित किया था, जो ''नेता'' द्वारा ''राष्ट्र'' की पहचान हड़प लिए जाने की हैरान करने वाली कोशिश को दिखाता है। इसी प्रकार, नागरिकों के अधिकारों पर जबर्दस्त हमला हो रहा है। कुछ अर्सा पहले, जब वामपंथ के समर्थन से यूपीए-1 की सरकार देश में चल रही थी, उसने जनता को अधिकार देने वाले तीन अति-महत्वपूर्ण कानून बनाए थे- वन-अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)। इस समय इन सभी कानूनों को बेमानी बनाया जा रहा है। हालांकि वन-अधिकार कानून कागज पर तो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वन (संरक्षण) संशोधन कानून 2023 को लाद दिया गया है, जिससे अब ''ढांचागत'' कामों के लिए (इजारेदार पूंजी द्वारा उपयोग के लिए) वन-भूमि का दिया जाना आसान हो गया है और यह ग्राम सभा के अनुमोदन बिना भी किया जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून में 2019 और 2023 में संशोधन कर, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी की अर्जियों की बढ़ती संख्या के खारिज किए जाने का रास्ता बना दिया गया है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को, जिसने मांग करने पर रोजगार का प्रावधान किया जाना अनिवार्य बनाने (या रोजगार न दे पाने की सूरत में काम मांगने वालों को मुआवजा दिए जाने) की व्यवस्था के जरिए, करोड़ों ग्रामीण परिवारों को जीवन रेखा मुहैया करायी थी, सीधे-सीधे निरस्त ही कर दिया गया है। इस कानून को, जिसे संसद में विस्तृत चर्चा के बाद और संसद के बाहर सार्वजनिक बुद्धिजीवी तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, संसद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, महज ध्वनि मत से और करीब-करीब बिना किसी चर्चा के ही, निरस्त कर दिया गया। जहां एक ओर जनता से अधिकार छीने गये हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के नाम वाली टार्गेटेड योजनाओं की गिनती बढ़ रही है। लोगों को भारत का नागरिक होने के अधिकार से जो हासिल होना चाहिए, उसे ये योजनाएं ऐसी कृपा में तब्दील कर देती हैं, जो दयालु प्रधानमंत्री (''नेता'') द्वारा उन पर की जाती है। अधिकारों के इस तरह छीने जाने के साथ ही साथ, ''कर्तव्यों'' पर बहुत जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, सरकार के अधिकारी नागरिकों के ''कर्तव्यों'' पर जोर देते कभी नहीं थकते हैं। और अब तो राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण सड़क को, जिस पर भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी लेते हैं, नाम बदलकर ''कर्तव्य पथ'' का नाम ही दे दिया गया है, ताकि लोग कर्तव्य पूरे करने की अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलें। फिर भी, राष्ट्र की अवधारणा के इस तरह सिर बल खड़ा किए जाने का सबसे विचित्र उदाहरण मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण (स्ढ्क) है, जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसे अनेक राज्यों में कराया जा रहा है, जहां इस समय चुनाव हो रहे हैं। आइए, पहले तो इस पर नजर डाल लें कि अब चुनाव आयोग का गठन किस तरह होता था। इससे पहले तक, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन, एक तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। लेकिन, भाजपा सरकार ने बिना कोई कारण दिए, उक्त व्यवस्था को बदल डाला और नया कानून बनाकर, मुख्य न्यायाधीश की जगह पर एक मंत्री को बैठा दिया, जिसका चुनाव अपने मंत्रिमंडल में से प्रधानमंत्री करेंगे। वर्तमान में इस तीसरे स्थान पर गृह मंत्री को रखा गया है। इस तरह चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाली वर्तमान तीन सदस्यीय कमेटी में प्रधानमंत्री का बहुमत है और तीन में से दो वोट उनके ही पास हैं। इस आयोग ने, अनाधिकृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के नाम पर, लोगों से असंभव दस्तावेज मांगने के जरिए, उनके नाम काटने शुरू कर दिए हैं। बेशक, कई दस्तावेज जिन्हें शुरूआत में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता के रूप में पात्रता के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के रूप में बहाल किया है। इसके बावजूद, लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ही, अनुमानत 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का 11 फीसद से ज्यादा होता है। और इनमें बहुत भारी संख्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की है, जिन्हें इस समय नव-फासीवादी संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बेशक, इन नामों के काटे जाने की अंतिमता में सुप्रीम कोर्ट ने जरा सा अड़ंगा लगा दिया है, जिसने नाम काटे जाने के शिकारों की शिकायतों की सुनवाई की अवधि कुछ बढ़ा दी है। लेकिन, आपने आप में स्वागत योग्य होने के बावजूद, यह नुकसान को जरा सा टालने का या उसे जरा सा कम करने का ही काम करता है, नुकसान को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। इस तरह, हमारे देश में आज प्रधानमंत्री और उनके नुमाइंदे ही यह तय कर रहे हैं कि वह ''जनता'' कौन सी होगी, जो सरकार को चुनेगी। बजाए इसके कि ''जनता'' सरकार को चुने, हमारे यहां सरकार ही ''जनता'' को चुन रही है। यह सारतः राष्ट्र की अवधारणा का ही सिर के बल खड़ा किया जाना है। यह हमें बर्टोल्ड ब्रेख्त की एक प्रसिद्ध कविता की याद दिलाता है- 'लगता है कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। क्यों न सरकार जनता को भंग कर दे और अपने लिए एक नयी जनता चुन ले!' यहां हम ब्रेख्त की व्यंग्यात्मक सलाह का शब्दशः परिपालन होता देख रहे हैं। लेकिन यह विडंबना नव-फासीवाद के सार को पकड़ती है और उस ''जनता-नेता'' रिश्ते के सिर के बल खड़ा किए जाने को सामने लाती है, जो नव-फासीवाद राष्ट्र की अवधारणा के सिर के बल खड़ा किए जाने पूरक के रूप में सामने आता है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नव-फासीवाद इस समय उतार पर है। उसे हर जगह धक्के लग रहे हैं। ट्रंप की ईरान में हार हुई है, जो उस देश पर अपने हमले के घोषित लक्ष्यों में से कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। हंगरी में चुनाव में विक्टर ओर्बान की हार हुई है। घोर-फासीवादी नेतन्याहू तक इस्राइल में अपनी हत्यारी परियोजना के लिए समर्थन खिसकते हुए देख रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पौपतघोला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

स्व. अरुणेश शर्मा 'पिंकी' की 6वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा, जनसेवा के योगदान को किया याद

नई दिल्ली।(साहिल गौड़) नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अरुणेश शर्मा 'पिंकी' की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी मार्केट, मिंटो रोड पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी राजेश शर्मा 'काले भाई' द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने स्वर्गीय अरुणेश शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अरुणेश शर्मा एक कर्मठ, जुझारू और जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नेता थे, जिनका जीवन सदैव समाज के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मसूद जिया, सतीश सैनी, मोहम्मद परवेज, विजय अरोड़ा, कुणाल कालरा, जितेंद्र 'बॉबी' और मुन्ना लाल सहित सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय अरुणेश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाज सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया।

गांधी नगर में एक्सप्रेसवे के नीचे अवैध पार्किंग पर सवाल, संगठित वसूली के आरोप

नई दिल्ली।(अशोका एक्सप्रेस) गांधी नगर क्षेत्र में देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे चल रही कथित अवैध पार्किंग को लेक र गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक पोस्टर/विजुअल के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि यहां वाहनों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है और यह गतिविधि संगठित तरीके से संचालित हो रही है। पोस्टर में दावा किया गया है कि संबंधित मामले में कार्रवाई अपेक्षित होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसमें कुछ अधिकारियों और विभागों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतों के बावजूद जांच या कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के नीचे पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि इसकी वैधता को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं, पोस्टर में यह भी कहा गया है कि मामले में जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी या कथित मिलीभगत के कारण स्थिति बनी हुई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित विभागों–पुलिस, नगर निकाय और प्रशासन–की ओर से इस विषय पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अवैध पार्किंग और वसूली पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट व्यवस्था और निगरानी तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता बताई गई है।

राजेन्द्र पाल गौतम को जन्मदिन पर बधाइयों की बौछार, राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली।(विजय शंकर चतुर्वेदी) पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र पाल गौतम को उनके जन्मदिन (26 अप्रैल) के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग (ट्रस्ट) के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे श्री गौतम के योगदान को याद करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने उनके सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी उन्हें विशेष रूप से बधाई संदेश दिया गया। वहीं, रिपब्लिकन मजदूर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी श्री गौतम के नेतृत्व और संघर्षशील छवि की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस मौके पर पत्रकार एवं महासचिव विजय कुमार भारती सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्री गौतम के आवास और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी। साथ ही, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं 'राष्ट्र टाइम्स' के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने भी श्री गौतम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना की। समर्थकों ने उनके दीर्घ राजनीतिक जीवन और जनसेवा के प्रति समर्पण को प्रेरणादायक बताया। जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की और उनके नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

आप नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, महात्मा गांधी को किया नमन

नई दिल्ली ।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी हैं। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश नहीं होने का एलान किया। उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है।

यह बेहद संवेदनशील मामला है – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम अपने देश की न्यायप्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम जो आजाद घूम रहे हैं तो उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बाते उस चिट्ठी में लिखी हैं जो कि हमने जज साहिबा को भेजी है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। सीबीआई की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल ने फैसला किया कि वह आगे इस मामले में न तो खुद पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील जिरह करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या कहा था?

केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को चार पन्नों का पत्र लिखकर यह जानकारी दी। पत्र में उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह निर्णय ले रहा हूं। मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हो सकता है कि इससे मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वे न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने लिखा अपने पत्र में अदालत में बहस के दौरान दी गई दलील दोहराते हुए कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।

गांधी के सत्याग्रह का हवाला

पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि यह फैसला केवल इसी मामले तक सीमित है। उन्होंने न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के वकालत करने के कारण हाईकोर्ट से स्थानांतरण की मांग की थी। केजरीवाल ने लिखा कि न्यायमूर्ति शर्मा की टिप्पणियों से उनकी अर्जी को न्यायिक और संस्थागत अपमान के रूप में लिया गया, जिसके बाद निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं रह गई है।

यह है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें आबकारी घोटाले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

इस अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर न्यायमूर्ति शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग की थी। 20 अप्रैल को अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि किसी राजनेता को न्यायपालिका पर अविश्वास फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि अब उन्हें विश्वास नहीं रहा कि न्यायमूर्ति शर्मा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएंगी।

सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे आप नेता

नई दिल्ली । आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई से अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने भी खुद को अलग कर लिया है।

मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश नहीं होने का एलान कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा, मेरी तरफ से भी कोई वकील पेश नहीं होगा। आपके ब'चों का भविष्य सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। ऐसे में मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

15 अरब डॉलर का गूगल एआई डेटा सेंटर, विशाखापत्तनम को ग्लोबल एआई हब बनाएगा भारत

नई दिल्ली/विशाखापत्तनम ।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (तारलुवाड़ा) में 15 अरब डॉलर के आगामी गूगल क्लाउड इंडिया एआई डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वैश्विक टेक दिग्गज गूगल, अदाणी ग्रुप और भारती एयरटेल की रणनीतिक साझेदारी में विकसित की जा रही है। इस निवेश से विशाखापत्तनम भारत का नया एआई आधारित डिजिटल गेटवे बनने जा रहा है।

परियोजना का विशाल स्तर और रणनीतिक क्षमता

इस एआई डेटा सेंटर का पैमाना भारत के मौजूदा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रमुख आंकड़े और साझेदारियां इस प्रकार हैं-

गीगावाट-स्केल एआई इकोसिस्टम- अदाणी ग्रुप के निदेशक जीत अदाणी ने बताया कि वर्तमान में पूरे भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.3 गीगावाट है। इसके मुकाबले, अकेले विशाखापत्तनम के इस एक ही लोकेशन पर 1 गीगावाट क्षमता वाला बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है।

दिग्गजों का गठजोड़- इसे अदाणीकनेक्स और भारती एयरटेल की डेटा सेंटर इकाई नेक्सट्रा के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है।

हरित ऊर्जा पर जोर- एयरटेल के पास पहले से ही देश भर में 120 से अधिक डेटा सेंटर्स का नेटवर्क मौजूद है और विशाखापत्तनम का यह नया प्रोजेक्ट पूरी तरह से नवीकरणीय (ऊर्जा से संचालित होगा। जीत अदाणी ने स्पष्ट किया कि एआई के संचालन की लागत सीधे तौर पर ऊर्जा की लागत से जुड़ी है, इसलिए किफायती ऊर्जा इस तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेगी।

वैश्विक कनेक्टिविटी और हार्डवेयर निर्माण

शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारत के डिजिटल ढांचे को मजबूत करने वाला कदम बताया और विशाखापत्तनम के एक एआई सिटी में तब्दील होने का विश्वास जताया।

सबमरीन केबल नेटवर्क- इस डेटा सेंटर के साथ विशाखापत्तनम से बिछाई जा रही अत्याधुनिक समुद्री केबल और मजबूत फाइबर नेटवर्क के कारण लेटेंसी (डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय) कम होगी। इससे भारत का संपर्क यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ और अधिक मजबूत हो जाएगा।

घरेलू विनिर्माण का आह्वान- भारत अब अपनी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मांग का लगभग 50 प्रतिशत खुद पूरा कर रहा है और मोबाइल फोन के निर्यात में बड़ी छलांग लगा चुका है। इसे देखते हुए मंत्री वैष्णव ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और अन्य तकनीकी कंपनियों से भारत में ही सर्वर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और एआई चिप्स का निर्माण करने का आग्रह किया है।

अर्थव्यवस्था और सेक्टोरल प्रभाव

इस निवेश का सीधा असर अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ने वाला है।

भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने रेखांकित किया कि विशाखापत्तनम, जो ऐतिहासिक रूप से एक समुद्री प्रवेश द्वार रहा है, अब डिजिटल इंडिया के लिए इंटेलीजेंस एज का गेटवे बनेगा। इस एआई डेटा सेंटर के जरिए देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, वैमानिकी, लॉजिस्टिक और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

एयरटेल के कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल के अनुसार, ग्रीन पावर और अल्ट्रा-लो लेटेंसी फाइबर नेटवर्क जैसी उनकी एकीकृत क्षमताएं इस विशाल एआई बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाएंगी।

आगे की राह

विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर का यह निवेश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राय के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की नीतियों की बदौलत विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट कंपनियों का यह गठजोड़ भारत को वैश्विक एआई रेस में मजबूती से खड़ा कर रहा है। लोअर एनर्जी कॉस्ट के कारण जब कंप्यूटिंग और एआई मॉडल की ट्रेनिंग सस्ती होगी, तो इसके परिणामस्वरूप देश भर में नवाचार बढ़ेगा और तकनीक पर आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

चुनावों के बाद कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं, मंत्रालय ने अटकलों को किया खारिज

नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विधानसभा चुनावों के समापन के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद ईंधन के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी।

सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पिछले दो महीनों में कच्चे तेल की लागत 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, -पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वह इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या बुधवार को पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। यह बयान उन अटकलों को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके कारण आंध्र प्रदेश जैसे रायों के कुछ हिस्सों में पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) शुरू हो गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, आसन्न मूल्य वृद्धि की अफवाहों के कारण आंध्र प्रदेश के कई शहरों में रविवार को 400 से अधिक पेट्रोल पंप सूख गए थे और कुछ आउटलेट्स पर मांग में 30-33 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई थी। शर्मा ने कहा, हमने कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग देखी है। हम इन सभी

जगहों पर राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सभी खुदरा आउटलेट्स की निगरानी की जा रही है और आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित हो और कोई कमी न हो।- उन्होंने जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया।

वित्तीय दबाव और कच्चे तेल की कीमतें

उल्लेखनीय है कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड चौथे वर्ष से अपरिवर्तित बनी हुई हैं। कीमतें अप्रैल 2022 की शुरुआत से स्थिर हैं। इनपुट लागत और पंप की कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, इन कंपनियों को रोजाना करीब 2,400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। विश्लेषकों ने पहले बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल की लागत के कारण चुनावों के बाद 25-28 रुपये प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि की संभावना जताई थी। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तब उछाल आया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने प्रभावी रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया - जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनियों में से एक है।

आपूर्ति पर्याप्त, कीमतें स्थिर

संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि देश में मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एलपीजी और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) सहित सभी ईंधनों का पर्याप्त भंडार है। हालांकि, वित्तीय दबाव स्पष्ट है। पिछले हफ्ते, शर्मा ने खुद बताया था कि वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के बावजूद पंप की कीमतें स्थिर रहने के कारण सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को पेट्रोल पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। कच्चा तेल, जो पिछले साल 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, इस महीने औसतन 114 अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा है। वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये है। सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि फिलहाल उपभोक्ताओं को बढ़ती वैश्विक कीमतों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

राशन वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए नए क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी होंगे, सीएम रेखा गुप्ता का आदेश

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्यूआर कोड और आधुनिक डिजिटल सुविधाओं वाले नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में विभाग के प्रदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी उन्नयन और जनसेवा संबंधी मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने 1 मई से हर शनिवार को 'जन शिकायत समाधान शिविर' लगाने का ऐलान किया है। शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सभी निर्धारित केंद्रों पर लगाए जाएंगे। शिविरों में सहायक आयुक्तों की उपस्थिति में सभी लंबित राशन कार्ड संबंधी शिकायतों का तत्काल निपटान किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वे स्वयं कुछ शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी और जांच करेंगी कि शिकायतों का सही ढंग से समाधान हो रहा है या नहीं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शिविर 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना की जागरूकता फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाएं। स्पष्ट रूप से बताया जाए कि लाभार्थी एक समय में केवल एक ही स्थान से राशन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में होने वाली अनियमितताओं जैसे कम वजन, देरी और अनधिकृत कटौती पर नाराजगी जताते हुए पूरे सप्लाई चेन में सख्त जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। दोषी डीलरों और सप्लायर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। सीएम ने सभी 1,943 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों को स्टैंडर्ड बनाने के निर्देश दिए। सभी दुकानों पर एक समान सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, स्व'छता बनाए रखी जाएगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

बैठक में फ्री एलपीजी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कुल 15,47,595 पात्र लाभार्थियों में से अभी 12,39,465 लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शेष सभी पात्र परिवारों को दिवाली तक योजना से जोड़ दिया जाए। उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने और जिला कार्यालयों में आधार केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि 100 प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित हो सके। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का फोकस केवल योजनाएं चलाने पर नहीं, बल्कि हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पारदर्शी, कुशल और सम्मानजनक तरीके से पहुंचाने पर है।

फालता एआरओ के तबादले के लिए ईसी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र; बमबाजी रोकने के लिए एनआईए को किया अलर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, चुनाव आयोग ने लापरवाही पर फालता विधानसभा के ज्वाइंट बीडीओ, जो फालता-144 विधानसभा क्षेत्र के एआरओ भी है, को हटाने और उनकी जगह पर नई नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं, आयोग ने एनआईए को चुनाव वाले दिन बमबाजी को लेकर अलर्ट भी किया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रशासनिक बदलाव और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए है। निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि फालता डेवलपमेंट ब्लॉक में तैनात संयुक्त बीडीओ (ज्वाइंट बीडीओ) सौरव हाजरा, जो 144-फालता विधानसभा सीट के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) भी है, उन्हें तुरंत वहां से हटाकर पुरुलिया मुख्यालय भेजा जाए। उनकी जगह राम्या भट्टाचार्य, जो वर्तमान में ओएसडी के पद पर है, को फालता में तैनात किया जाए। आयोग का मानना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसे बदलाव जरूरी है।

एनआईए को चुनाव आयोग ने दिया विशेष निर्देश

इसके साथ ही आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी खास निर्देश दिए है। आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह के बम या हिंसक गतिविधियों का इस्तेमाल न होने दिया जाए। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब हाल ही में राज्य के कई इलाकों से कच्चे बम बरामद हुए है और एक मामूली विस्फोट की खबर भी सामने आई थी।

दक्षिण 24 परगना जिले में भारी संख्या में मिला कच्चा बम

जानकारी के अनुसार, 26 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में एक व्यक्ति के घर से पुलिस ने बड़ी संख्या में कच्चे बम बरामद किए थे। आरोप है कि वह व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़ा हुआ है। इसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने कुल 79 कच्चे बम मिलने के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरे चरण के मतदान के लिए आयोग की तैयारी

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार किसी भी कीमत पर चुनाव के दौरान या उसके बाद हिंसा नहीं होने दी जाएगी। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही सतर्क कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है।

बता दें कि, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हो चुका है, जबकि दूसरा चरण बुधवार को होना है। आयोग की कोशिश है कि मतदाता बिना डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।

नगर निगम चुनाव में भाजपा ने सभी 15 निगमों पर जमाया कब्जा

अहमदाबाद। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने अब तक 15 में से नौ नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। राज्य में मंगलवार, 28 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी रही। राज्य चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, करमसद-आनंद, नडियाद, नवसारी, वापी, सूरत और मोरबी के नगर निगमों में कुल सीटों के आधे से अधिक पर जीत दर्ज की है। मोरबी नगर निगम में भाजपा ने सभी 52 सीटों पर कब्जा किया है। रविवार, 26 अप्रैल को 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को राज्य के सबसे बड़े चुनावी अभ्यासों में से एक माना गया। इसमें लगभग 9,200 सीटों पर 4.18 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता शामिल थे। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नगर निगमों के लिए 55.1 फीसदी, नगर पालिकाओं के लिए 65.53 फीसदी, जिला पंचायतों के लिए 66.64 फीसदी और तालुका पंचायतों के लिए 67.26 फीसदी मतदान हुआ। नगर निगमों में, कच्छ जिले के नवगठित गांधीधाम में सबसे कम 46.03 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। वहीं, वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 फीसदी मतदान हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में 51.81 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर सहित नौ नवगठित नगर निगमों में पहली बार मतदान हुआ।

- फतेहपुर में दलित बेटी के दोषी मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, इसलिए बचाया जा रहा- अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा, मुझे खुशी है कि हमारा डेलीगेशन उस परिवार से मिला। पांच लाख से हम लोगों ने मदद की। लेकिन, न्याय की बात अभी भी अधूरी है। परिवार को न्याय मिले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे लगे है, वह वापस लें। प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ, फतेहपुर में एक बेटी के साथ क्या हुआ और करने वाले भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पदाधिकारी है। इन्हें मुख्यमंत्री खुद बचा रहे है इसलिए बचा रहे है क्योंकि उनका ही स्वजातीय है। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कमिश्नर के परिवार के लोग कहां-कहां पोस्ट हो रहे है। क्या आगरा नोएडा में ऐसे ही पोस्टिंग मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे। हमारे मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहते हैं, क्या यही सनातनी परंपरा है कि एक पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान होगा। अंत में सब मरोगे इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ।

सिक्किम को मिली 4,000 करोड़ की सौगात

पूर्वोत्तर भारत की अष्टलक्ष्मी, अब एक्ट ईस्ट नहीं एक्ट फास्ट का समय- पीएम मोदी

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के गंगटोक स्थित पालजोर स्टेडियम से राज्य के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि सिक्किम इस प्रगति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अब केवल नीतियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के लिए हमने न केवल एक्ट ईस्ट नीति अपनाई, बल्कि अब हम एक्ट फास्ट (तेजी से काम करना) के दृष्टिकोण पर चल रहे है। आज स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा क्षेत्र में जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, वे इसी गति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की सराहना करते हुए इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने दशकों तक सिक्किम और पूर्वोत्तर की विकास संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही इस क्षेत्र में विकास ने वास्तविक रफ्तार पकड़ी है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो पहले काफी उपेक्षित थीं। सिक्किम के युवाओं की खेल प्रतिभा की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया पहल के जरिए राज्य की प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है।

आईएसआईएस के निशाने पर हिंदू :जिहाद के नाम पर बनाया जा रहा निशाना, मीरा रोड चाकू कांड पर भड़के फणडवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में हुए चाकू से हमले के मामले में अब जांच ने गंभीर और बड़ा मोड़ ले लिया है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला लोन वुल्फ यानी अकेले किए गए हमले जैसा लगता है और शुरुआती जांच में आरोपी के घर से कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी के व्यवहार और मिले सबूतों से ऐसा संकेत मिलता है कि वह खुद को कट्टर विचारों से प्रभावित कर चुका था। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी की सोच जिहाद के नाम पर हिंदू धर्म को निशाना बनाने की ओर झुकी हुई थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, आरोपी के घर से कुछ किताबें और संदिग्ध सामग्री मिली है, जो गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वाली हो सकती है।

उन्होंने बताया कि आरोपी पहले अमेरिका में रहता था और हाल ही में भारत लौटा था। फडणवीस ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की सोच रखता था और इसी मानसिकता के चलते उसने यह हमला किया। उन्होंने आगे बताया कि इस पूरे मामले की जांच सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाएंगी कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जांच का दायरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि आरोपी किस तरह से प्रभावित हुआ और क्या इसके पीछे कोई और लोग या संगठन शामिल है।

महिला आरक्षण पर घमासान- कांग्रेस का पीएम पर बड़ा हमला, कहा- बुलाएं सर्वदलीय बैठक, 2029 से ही लागू हो कोटा

नई दिल्ली।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पार्टी का कहना है कि सरकार को लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के साथ ही महिला कोटा लागू करने पर चर्चा करनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि अब समय आ गया है जब प्रधानमंत्री अपने पापों का प्रायश्चित करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश की महिलाओं का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव अभियान खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की

एकजुटता के कारण पीएम की यह चाल नाकाम हो गई है। अब प्रधानमंत्री को वह करना चाहिए जिसकी मांग विपक्ष मार्च 2026 से लगातार कर रहा है।

2029 से लागू करने की मांग

रमेश ने कहा कि सरकार को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। इस बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने पर बात हो। उन्होंने कहा कि इसे 2029 से मौजूदा सीटों पर ही प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि इस अधिनियम को 16 अप्रैल 2026 की देर रात धमाहट में अधिसूचित किया गया था। कांग्रेस नेता के मुताबिक मौजूदा संख्या के साथ आरक्षण देना संभव भी है और जरूरी भी। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण कभी मुख्य मुद्दा था ही नहीं।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का असली मकसद केवल परिसीमन करना था। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए परिसीमन का खेल रचा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीएम को अब अपनी रणनीति बदलनी चाहिए।

कांग्रेस ने मांग की है कि मानसून सत्र या उससे पहले बिल लाकर मौजूदा सीटों पर ही कोटा लागू हो। विपक्ष शुरू से ही महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन थोपने का विरोध कर रहा है।

बीजेपी के बंगाल गुड बाय पोस्ट पर भड़की टीएमसी, बोली- बंगाल की पहचान मिटाने की खुली धमकी

बंगाल। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की बंगाल गुड बाय टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और विपक्षी पार्टी पर राज्य को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद सीएम ममता के बाहर जाते हुए एक ग्राफिक शेयर किया था, जिस पर लिखा था, बंगाल गुड बाय। टीएमसी ने इस सोशल मीडिया पोस्ट को पश्चिम बंगाल की संस्कृति और भाषा के लिए एक खुली धमकी माना है और आरोप लगाया है कि बीजेपी रा'य के लोगों को एक जैसा बनाना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ बांग्ला-विरोधी तंज को दोहराया। टीएमसी ने पोस्ट किया बीजेपी बंगाल में पल्टाना दरकार और पोरिबर्तन के नारे लगाते हुए आई थी। अब वे खुले तौर पर बंगाल गुड बाय कह रहे हैं। यह बंगाल की पहचान से जुड़ी हर चीज को मिटाने की एक खुली धमकी है। आइए, हम यह साफ कर दें कि बंगाल गुड बाय का असली मतलब क्या है- गुड बाय, बंगाल की संस्कृति; गुड बाय, बंगाली भाषा; गुड बाय, बंगाल के महापुरुष; गुड बाय, बंगाल का इतिहास; गुड बाय, बंगाली साहित्य; गुड बाय, बंगाल की विरासत; गुड बाय, बंगाली खाना। बीजेपी बंगाल पर राज नहीं करना चाहती। वे इसे खत्म करना चाहते हैं। वे हमारे मूल स्वरूप को ही बदलना चाहते हैं; हमारी पहचान को अपने एक जैसे, एकछत्र रूप से बदलना चाहते हैं, जिसमें बंगाल की अपनी खासियत, बंगाल के गौरव या बंगाल की आत्मा के लिए कोई जगह न हो। वे उस चीज को बदलना चाहते हैं जो बंगाल को बंगाल बनाती है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस बांग्ला-विरोधी बीजेपी को हमारी पहचान मिटाने मत दो। इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पोस्ट में यह लिखा था।

डिवाइडर से टकराई तेज स्पीड कार; पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत

कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर पिपली-शाहबाद के बीच में गांव खानपुर कोलियां के पास हुए भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में बेटा घायल हो गया है। हादसा दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही एक कार के अचानक डिवाइडर से टकराने पर हुआ है। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान बृजभूषण (83), उसकी पत्नी कांता (80) और भारत के रूप में हुई है, वह दिल्ली के नांगलोई के निवासी बताए जा रहे है। वहीं बृजभूषण का बेटा तरुण (53) इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है।

ईरान बोला- ट्रम्प का दबाव नहीं सहेंगे- अमेरिका अब दूसरे देशों पर फैसले थोपने की स्थिति में नहीं

तेहरान। ईरान ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाई-निक ने सरकारी टीवी से कहा कि वे ट्रम्प का दबाव नहीं सहन करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका, होर्मुज को खोलने से जुड़े ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्धविराम लागू है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है, उसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तीन ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए रविवार को एक नया प्रस्ताव दिया था।

इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें थीं-

1. अमेरिका-इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले
2. फिर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे, होर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो
3. सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो

हालांकि ट्रम्प इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रम्प सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए बिना होर्मुज खोला, तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए।

शंभू-अंबाला रेल ट्रैक पर ब्लास्ट का मामला सुलझा, हथियारों सहित 4 गिरफ्तार

पटियाला। पटियाला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर बॉर्डर पार चल रहे एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मॉड्यूल के 4 प्रोफेशनल दोषियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में जंगी हथियार, विस्फोटक और मॉडर्न टेक्निकल डिवाइस बरामद किए है। इस ऑपरेशन से हाल ही में शंभू-अंबाला रेलवे रूट पर हुए बम ब्लास्ट की गुत्थी भी सिर्फ 12 घंटे में सुलझ गई है। डीआईजी पटियाला रेंज कुलदीप सिंह चहल और एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह खालसा (मुख्य लीडर), कुलविंदर सिंह बग्गा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है। ये आरोपी खालिस्तानी सोच से प्रभावित हैं और चक्रदा वहिर चक्रवर्ती, अटारी नाम के संगठन से जुड़े है। ये मलेशिया और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों ने कबूल किया है कि 27 अप्रैल की रात शंभू-अंबाला रेलवे लाइन पर हुए धमाके के पीछे उनका हाथ था, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था। उनका मकसद पंजाब की मुख्य रेलवे लाइनों और सार्वजनिक जगहों को उड़ाकर राज्य की शांति भंग करना और आतंक का माहौल बनाना था।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक जिंदा बम, 2 पिस्तौल (30 बोर और 32 बोर), आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, लैपटॉप और मलेशिया में बैठे हैंडलर्स से बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे टेक्निकल उपकरण बरामद किए है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत पटियाला थाने में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उनके विदेशी संपर्कों और दूसरे संभावित टारगेट के बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी।

देश के कई हिस्सों में पारा पहुंचा 45डिग्री के पार, केंद्र ने राज्यों को जारी किए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। देशभर में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। सूरज की तपिश अब जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ती हुई इस गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस कि लू के प्रकोप से श्रमिकों को बचाने के लिए काम के घंटों में बदलाव किया जाना चाहिए। दोपहर की कड़ी धूप के दौरान काम को रोककर सुबह या शाम के समय में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है। निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और खदानों में ठंडे पानी, पर्याप्त छाया और विश्राम की व्यवस्था अनिवार्य होगी। एक ही व्यक्ति पर अधिक दबाव न पड़े, इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने की सलाह दी गई है ताकि सभी को पर्याप्त ब्रेक मिल सके।